(d) and (e) Due to resources constraints, there is no special plan for construction of more houses in Delhi. However, within the funds provided for construction of General Pool accommodation, priority is given to Delhi.

Allotment of Houses by GDA to SCs/STs

1426. CHOWDHRY HARI SINGH : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) how many houses in every category have been allotted by Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad, U.P. to the scheduled castes and scheduled tribes during 1990---93; and

(b) what was the total number of applicants who were registered for getting houses in the above period of the people of the scheduled castes and scheduled tribes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.K. THUNGON) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Declaration of Narmada Valley as National Project

1427. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether the Government of Gujarat has requested the Central Government to declare Narmada Valley as a national project; and

(b) if so, the reaction of Central Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.K. THUNGON) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि

1428. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सिंचाई क्षमता पैदा करने के संबंध में अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बड़ी और मझोली परियोजनाओं की अपेक्षा छोटी परियोजनाओं में प्रति हैक्टेयर सिंचाई क्षमता पर लागत कम आती है;

(ख) क्या सरकार ने कम लागत के संबंध में तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना मे दिशा परिवर्तन किया है; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई क्षमता के संबंध मे बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार की परियोजनाओं के लिए अलग-अलग क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा इनमे से प्रत्येक पर अलग-अलग अनुमानत: कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० कं० थुंगन) : (क) केवल प्रत्यक्ष निवेश पर विचार करने पर बृहद और मध्यम परियोजनाओं की तुलना में लघु सिंचाई स्कीमें प्रति हैक्टेयर लागत आधार पर सस्ती प्रतीत होती है। तथापि यदि लघु सिंचाई स्कीमों में नलकूपों/पम्पसैटों को ऊर्जा

प्रदान करने हेतु संसाधन की आनुपातिक लागत को ध्यान में रखा जाता है, तो लघु स्कीमें भी बृहद और मध्यम परियोजनाओं की तुलना में प्रति हेक्टेयर लागत आधार पर सस्ती नहीं हैं । इसके अतिरिक्त, बृहद और मध्यम परियोजनाओं की उपयोग अवधि लघु स्कीमों से कहीं अधिक है ।

(ख) बृहद और मध्यम और लघु स्कीमें प्रतियोगी नहीं है बल्कि स्थान विशिष्ट होती हैं और किसी भी क्षेत्र में इष्टतम जल संसाधन विकास में सफलता प्राप्त करने हेतु एक दूसरे के लिए सहायक हैं । किसी विशेष स्थान पर निर्मित की जाने वाली परियोजना के क्षेत्र और आकार का निर्धारण उस क्षेत्र के स्थलाकृति विज्ञान, जल उपलब्धता, जल वैज्ञानिक और जल भूवैज्ञानिक विशेषताओं और सिंचित किये जाने वाले क्षेत्र द्वारा किया जाता है । तदनुसार, सरकार प्रत्येक प्रकार की परियोजना/स्कीम को उपयुक्त महत्व दे रही है ।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) के दौरान बृहद और मध्यम परियोजनाओं से 5.067 मिलियन हैक्टेयर और लघु स्कीमों से 10.711 मिलियन हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने क लक्ष्य का प्रताव किया गया है जिसमें बृहद और मध्यम परियोजनाओं के लिए 22414.53 करोड़ रूपए और लघु स्कीमों के लिए 5977.26 करोड़ रुपये का परिव्यय सम्मिलित है ।

Completion of Major/Minor Irrigation Projects in Karnataka

1429. SHRI B.K. HARIPRASAD : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether the Draft document for Eighth Five Year Plan has cautioned a go-slow on taking up new major/minor irrigation projects till the completion of many on-going major/minor irrigation projects;

(b) if so, whether the Planning Commission has also identified a few major/minor irrigation projects which are still unfinished despite the fact that these projects are in the making for more than forty years now causing cost and time over runs;

(c) whether it is also a fact that the work started on the Bhadra (1947) Tungabhadra Dam & LBC (1945), Manchandbala (1969) and Votehole (1971) projects in Karnataka sanctioned long back, is still incomplete; and

(d) if so, whether Central Government would ensure that these projects are provided for and completed during Eighth Five Year Plan period ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.K. THUNGON) : (a) The Eighth Plan strategy *inter-alia*, envisages that completion of ongoing projects with a strict prioritisation will be the first charge on funds under major and medium irrigation sector. No new projects will be included unless the needs of the ongoing projects are fully met, and if at all done, these should be restricted to medium schemes benefitting tribal and drought prone areas. It is also envisaged therein that priority should be given for speedy completion of large number of on-going surface water minor irrigation schemes.

(b) No, Sir. However 4 major projects namely Bhadra, Tungabhadra Dam and Left Bank Canal, Harishchandrasagar and Barrage & Irrigation system of DVC & 1 medium pro-